

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जेनोसाइड कन्वेंशन

प्रलिस के लयि:

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जेनोसाइड कन्वेंशन, इंडियाज़ एंगेजमेंट वदि आईसीजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, द्वितीय वशिव युद्ध, 1998 रोम स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ।

मेन्स के लयि:

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये [अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय](#) (International Court of Justice-ICJ) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ।

- यूक्रेन ने रूस पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया है कि "यूक्रेन के लुहान्स्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जेनोसाइड की घटनाएँ हुई हैं" तथा इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता हेतु रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है ।
- यह विवाद रोकथाम और जेनोसाइड के अपराध की सज़ा पर 1948 के कन्वेंशन से संबंधित है ("जेनोसाइड कन्वेंशन") ।

प्रमुख बडि

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में:** ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है ।
 - संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है ।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया ।
- **प्रवर्गामी:** ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) का उत्तराधिकारी है, जिसे राष्ट्र संघ के माध्यम से और उसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था ।
 - PCIJ की स्थापना फरवरी, 1922 में नीदरलैंड के द हेग में पीस पैलेस में की गई ।
 - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और PCIJ को क्रमशः संयुक्त राष्ट्र और ICJ द्वारा प्रतस्थापित किया गया था ।
 - PCIJ को औपचारिक रूप से अप्रैल 1946 में भंग कर दिया गया था और इसके अंतिम अध्यक्ष, अल सल्व्वादोर के न्यायाधीश जोस गुस्तावो ग्युरेरो, ICJ के पहले अध्यक्ष नियुक्त किये गए ।
- **ICJ की भूमिका:** यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है ।
- **पहला मामला:** पहला मामला, ब्रिटन द्वारा अल्बानिया के विरुद्ध लाया गया था और यह 'कोरफु चैनल' से संबंधित था, जो क्युरोपीय मेनलैंड पर कोरफु एवं अल्बानिया के ग्रीक द्वीप के बीच आयोनियन सागर का संकीर्ण जलडमरूमध्य है, को मई 1947 में प्रस्तुत किया गया था ।
- **ICJ प्रशासन:** न्यायालय के न्यायाधीशों को 'रजिस्ट्री' द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो कि ICJ का एक प्रशासनिक अंग है ।
- **आधिकारिक भाषाएँ:** अंग्रेज़ी और फ्रेंच ।
- **ICJ क्षेत्राधिकार:** UN के सभी सदस्य स्वयं ही ICJ के पक्षकार हैं, हालाँकि यह स्वचालित सदस्यता उनसे जुड़े विवादों पर ICJ के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करती है ।
 - ICJ को अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों ।
 - ICJ का निर्णय अंतिम एवं तकनीकी रूप से मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है ।
 - हालाँकि ICJ के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई विधि नहीं है और यह पक्षकार देशों की इच्छा पर निर्भर करता है ।

ICJ के न्यायाधीश कसि प्रकार चुने जाते हैं?

- ICJ में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के लिये चुना जाता है।
- नरिवाचति होने के लिये एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है और इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रायः कभी-कभी मतदान प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चुनाव होते हैं।
 - न्यायालय के एक-तर्हिई सदस्यों को प्रति तीन वर्ष में चुना जाता है।
- अदालत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को गुप्त मतदान द्वारा तीन वर्ष के लिये चुना जाता है।
 - न्यायाधीश पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होते हैं।
- **ICJ में भारतीय न्यायाधीश:** चार भारतीय अब तक ICJ के सदस्य रहे हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दलवीर भंडारी वर्ष 2012 से ICJ में काम कर रहे हैं।
 - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक ने वर्ष 1989-91 तक ICJ में कार्य किया।
 - भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नार्गेन्द्र सहि वर्ष 1973-88 तक ICJ में रहे।
 - सर बेनेगल राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, वर्ष 1952-53 तक ICJ के सदस्य थे।

ICJ के साथ भारत के जुड़ाव का इतिहास:

- भारत छह मौकों पर ICJ के मामलों में पक्षकार रहा है, जिनमें से चार में पाकिस्तान भी शामिल रहा है। ये हैं:
 - भारतीय क्षेत्र पर मार्ग का अधिकार (पुर्तगाल बनाम भारत, 1960 को समाप्त हुआ)।
 - आईसीओ (ICAO) परिषद के क्षेत्राधिकार से संबंधित अपील (भारत बनाम पाकिस्तान, प्रणित 1972)।
 - युद्ध के पाकिस्तानी कैदियों का परीक्षण (पाकिस्तान बनाम भारत, 1973 में समाप्त हुआ)।
 - 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना (पाकिस्तान बनाम भारत, 2000 का समापन)।
 - परमाणु हथियारों की होड़ को जल्द-से-जल्द समाप्त करने और परमाणु नरिस्त्रीकरण (मार्शल द्वीप बनाम भारत, 2016 को समाप्त) से संबंधित बातचीत करने के लिये प्रतिबद्ध।
 - कुलभूषण जाधव (भारत बनाम पाकिस्तान, 2019 का समापन)।

जेनोसाइड कन्वेंशन:

- जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सज़ा पर कन्वेंशन (जेनोसाइड कन्वेंशन) अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उपकरण है जसि पहली बार जेनोसाइड के अपराध के लिये संहिताबद्ध किया गया है।
- जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी।
- यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किये गए अत्याचारों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की 'फरि कभी नहीं (Never Again)' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- जैसा कहिम जानते हैं, इसे अपना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है।
- कन्वेंशन में नरिधारित जेनोसाइड के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जसिमें वर्ष 1998 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संधि भी शामिल है।
- महत्वपूर्ण रूप से कन्वेंशन राज्य पारटियों पर जेनोसाइड के अपराध को रोकने और दंडित करने हेतु कानून बनाने तथा अपराधियों को दंडित करने "चाहे वे संवैधानिक रूप से ज़िम्मेदार शासक, सार्वजनिक अधिकारी या नज़ी व्यक्ति ही क्यों न हों" से संबंधित है (अनुच्छेद IV)।
 - इस दायित्व को, नरसंहार प्रतिषिद्ध के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के मानदंडों के रूप में भी देखा जाता है तथा इसलिये यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी है चाहे उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि की हो या नहीं।
- भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर

	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC)
स्थापना	वर्ष 1945	वर्ष 2002
UN संबंध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जसि आमतौर पर 'वर्षि न्यायालय' के रूप में जाना जाता है।	स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है।
मुख्यालय	हेग (नीदरलैंड्स)	हेग (नीदरलैंड्स)
मामलों के प्रकार	यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा वर्षि एजेंसियों द्वारा नरिदषित कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।	व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमा
वर्षि-वस्तु	संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संधि	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध

- सेबी एक अर्द्ध-वधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो वनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नयिम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है।
- यह तीन श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करता है-
 - **जारीकर्त्ता**- एक बाज़ार उपलब्ध कराना जिसमें जारीकर्त्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं।
 - **नविशक**- सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करके।
 - **मध्यवर्ती/बचौलियि**- बचौलियों के लिये एक प्रतस्पर्धी पेशेवर बाज़ार को सक्रम करके।
- प्रतभूतकानून (संशोधन) अधनियम, 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशिकी कसिी भी मनी पूलगि योजना को वनियमति करने तथा गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्तिको संलग्न करने में सक्रम है।
- सेबी के अध्यक्ष के पास "तलाशी/जाँच और ज़बती संबंधी ऑपरेशन" का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड कसिी भी प्रकार के प्रतभूतलेन-देन के संबंध में वयक्तया संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रकिर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।
- सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहति सामूहिक नविश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा वनियमन का कार्य करता है।
- यह स्व-नयामक संगठनों को बढ़ावा देने उन्हें वनियमति करने और प्रतभूतबाज़ारों से संबंधति धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतबिंधति करने के लिये भी कार्य करता है।



मुद्दे और संबंधति चतिाँ

- हाल के वर्षों में सेबी की भूमिका और अधिक जटलि हो गई है।
- बाज़ार के आचरण के नयिमन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि वविकपूर्ण नयिमन पर कम।
- सेबी की वैधानिकि प्रवर्तन शक्तियाँ अमेरिका और ब्रटिन में इसके समकक्षों की तुलना में अधिक हैं क्यौंक गंभीर आर्थिक क्षति के लिये दंड देने के मामले में यह तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है।
- यह आर्थिक गतिविधि पर गंभीर प्रतबिंध लगा सकता है, ऐसा नवारक नरिध कसिी तरह के संदेह के आधार पर कया जाता है।
- अधीनस्थ कानून बनाने के लिये सेबी अधनियम के व्यापक वविकाधिकार के रूप में इसकी **वधायी शक्तियाँ नरिपेक्ष** हैं।
- बाज़ार के साथ पूर्व परामर्श का घटक और वनियमों की समीक्षा की एक प्रणाली (जो यह देखने के लिये तैयार की गई है कक्या वनियम वयक्त कयि गए उदेश्यों को पूरा करते हैं) काफी हद तक अनुपस्थति है। परणामस्वरूप नयामक की शंका व्यापक है।
- वनियमन, चाहे वे नयिम हों या प्रवर्तन, वशिष रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में परपूरणता से बहुत दूर है।
- प्रतभूतियों की पेशकश करने वाले दस्तावेज़ असाधारण रूप से वजन में भारी होते हैं और उनके औपचारिक अनुपालन हेतु उनकी उच्च गुणवत्ता के वास्तविकि प्रकटीकरण के बजाय संख्या को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

आगे की राह

- वास्तव में एक अभवित्तिकि प्रवर्तन की आवश्यकता है क्यौंक बाज़ार के बारे में सैकड़ों की संख्या में ऐसी जानकारी उपलब्ध हैं जो दर्शाती हैं क बाज़ार अपराधियों से भरा हुआ है जिसके चलते सख्त कार्रवाई और गंभीर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- बाज़ार को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस संदर्भ में सेबी को गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता है। फंडस के आकार में वृद्धिकभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकती और न ही यह प्रदर्शति कर सकती है क बाज़ार वनियमन के इस खंड/क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन हो रहा है।
- सेबी को अपने संगठन के अंतर्गत मानव संसाधन और इससे संबंधति मामलों पर वशिष ध्यान देना चाहयि।
- वायदा बाज़ार आयोग के सेबी में वलिय के बाद वरिष्ठ कर्मचारियों का संरेखण और नयुक्तिका कार्य का एक खुला क्षेत्र बना हुआ है।
- नरितर नगिरानी और बाज़ार की खुफिया जानकारी में सुधार के साथ प्रवर्तन को मज़बूत कया जा सकता है।
- भारत के वत्तीय बाज़ार एक-दूसरे से वभिाजति हैं। वत्तीय उत्पादों की ओवरलैपिंग के मामले में एक नयामक को दूसरे की वफिलता के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
 - इस संदर्भ में एक एकीकृत वत्तीय नयामक, ओवरलैप तथा अपवर्जति सीमाओं दोनों के वषिय में उत्पन्न गतिरिध को दूर करने का प्रयास

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग

प्रलमिस के लिये:

राज्यसभा, अनुच्छेद 80, संविधान की चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, नज़ि सदस्य वधियक।

मेन्स के लिये:

नज़ि सदस्य वधियक, भारतीय संसद में केंद्रशासति प्रदेशों का प्रतिनिधित्व।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चंडीगढ़ नगर नगिम ने संविधान के [अनुच्छेद 80](#) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उसके पार्षद [राज्यसभा](#) में एक प्रतिनिधि भेज सकें।
- भारत के संविधान का [अनुच्छेद 80](#) राज्यों की परिषद की संरचना से संबंधित है जिसे **उच्च सदन (राज्य सभा)** कहा जाता है।
- अभी तक चंडीगढ़ का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

प्रस्तावति वधियक की मांग:

- बलि ([नज़ि सदस्य वधियक](#)) के द्वारा एक प्रावधान जोड़ने की मांग की गई है जिसके तहत **राज्य परिषद में केंद्रशासति प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधि एक नरिवाचक मंडल** द्वारा चुना जाएगा।
 - नरिवाचक मंडल में संविधान के अनुच्छेद 80 में पंजाब नगर नगिम (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 के तहत गठित चंडीगढ़ नगर नगिम के नरिवाचति सदस्य शामिल होने चाहिये।
- '**एंट्री 32, चंडीगढ़**' के साथ संविधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन की मांग की गई है।
 - इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासति प्रदेश से राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या शामिल है।

चंडीगढ़ की स्थिति:

- चंडीगढ़ बिना विधानसभा वाला एक केंद्रशासति प्रदेश है और नमिन सदन या लोकसभा में संसद सदस्य (MP) की एक सीट है।
- चंडीगढ़ के निवासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर पाँच साल में एक सांसद का चुनाव करते हैं।
 - पुद्दुचेरी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली केंद्रशासति प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जबकि लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली-दमन एवं दीव, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का उच्च सदन (राज्यसभा) में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

कानूनी आपत्तियाँ:

- नरिवाचति नगर नगिम पार्षद उच्च सदन (राज्यसभा) के लिये सदस्य का चयन करने हेतु नरिवाचक मंडल का गठन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नगर नगिम की शक्तियों से परे है।
 - वर्ष 1966 से 1990 के बीच दलिली में राज्यसभा के लिये सांसदों का चयन दलिली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के सदस्यों द्वारा किया गया था।
 - महानगर परिषद (Metropolitan Council) और नगर नगिम (Municipal Corporation) में अंतर है।
 - विधानमंडलों के नरिवाचक मंडल और एमसी पार्षदों के नरिवाचक मंडल में भी अंतर है।
 - साथ ही चंडीगढ़ में दलिली की तरह कोई विधानसभा नहीं है, जो एक केंद्रशासति प्रदेश भी है, और शहर में एक महानगरीय परिषद का भी अभाव है जो राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद है।
- साथ ही राज्यसभा सांसद का चयन करना नगर नगिम के कार्यों की सूचीबद्धता के दायरे से बाहर है।
- नागरिक निकाय (Civic Body) के कार्यों को सूचीबद्ध करि गए कार्यों के दायरे से विस्तारित किया जाना संभव नहीं होगा तथा यह नगर नगिम के ऐसे किसी भी संविधानिक आदेश के खिलाफ होगा।
 - जैसा कि नागरिक निकाय ने संशोधन को अपनी सहमति दी है, केंद्रशासति प्रदेश प्रशासन इसे आगे विचार के लिये गृह मंत्रालय को भेजेगा

और फरि इसे संसद को भेजा जाएगा।

नजी सदस्य वधियक:

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक नजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।
- इसका प्रारूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है।
- सरकारी वधियक/सार्वजनिक वधियकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, नजी सदस्यों के वधियकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है तथा उन पर चर्चा की जा सकती है।
- कई वधियकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग वधियकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।
- नजी सदस्यों के वधियकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति/ऐसे सभी वधियकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।
- सदन द्वारा इसकी अस्वीकृत का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- चर्चा के समापन पर वधियक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

सरकारी वधियक बनाम नजी वधियक

सरकारी वधियक	नजी वधियक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह वपिष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी वधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सरकारी वधियक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिये।	इस वधियक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये।
इसे संबंधित विभाग द्वारा वधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मनिमि एशोरड रटिरन स्कीम: पीएफआरडीए

प्रलिमिंस के लिये:

मनिमि एशोरड रटिरन स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल पेंशन सिस्टम।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिये न्यूनतम सुनिश्चित रटिरन योजना का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

[पेंशन नधि नियामक और विकास प्राधिकरण \(PFRDA\)](#) ने एक गारंटीड रटिरन स्कीम 'मनिमि एशोरड रटिरन स्कीम (MARS) प्रस्तावित की है, जो बचतकर्त्ताओं और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को उनके नविश का विकल्प प्रदान करेगी।

- पेंशन नियामक की यह पहली योजना होगी जो नविशकों को **गारंटीकृत रटिरन** प्रदान करेगी।
- प्रबंधन के तहत भारत की पेंशन संबंधी संपत्ति पिछले ही 7 लाख करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर चुकी है और इसके वित्त वर्ष 2021-22 के मार्च के अंत तक 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है।
- PFRDA ने वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए के एयूएम (प्रबंधन के तहत संपत्ति) का लक्ष्य रखा है।

MARS के तहत PFRDA का प्रस्ताव:

- **परचिय:**

- यह एक अलग योजना है जो **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)** के तहत ग्राहकों को गारंटीकृत न्यूनतम दर की वापसी की पेशकश कर सकती है, खासकर उन्हें जो जोखिम उठाने से बचते हैं।
 - एनपीएस वर्तमान में मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर वार्षिक रटिर्न देता है।
- वास्तविक रटिर्न बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी कमी को प्रायोजक द्वारा पूरा करने के साथ ही अधिशेष ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा।
- **पेश किये जाने वाले विकल्प:**
 - **फकिस गारंटी ऑप्शन:** निश्चित गारंटी ऑप्शन के तहत संचय चरण के साथ गारंटीकृत रटिर्न तय किया जाता है।
 - **फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन:** फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन के तहत रटिर्न की गारंटी दर बचत चरण के साथ तय नहीं होती है।
 - फ्लोटिंग गारंटी **सेवानिवृत्त 1 वर्ष की ब्याज दर** के विकास पर निर्भर करती है।
- **लॉक-इन पीरियड:**
 - **लॉक-इन पीरियड** प्रत्येक योगदान पर लागू हो सकता है और उस अवधि के आधार पर लागू किया जाएगा जब से वह योगदान दिया गया है। यह लचीलेपन के लिये कई **लॉक-इन पीरियड** विकल्पों (या कंपति गारंटी अवधि) पर भी विचार कर सकता है।
 - **नक़ासी का सीधे लॉक-इन पीरियड से जुड़े होने की संभावना** है। सब्सक्राइबर के पास लॉक-इन पीरियड के बाद वापसी या नविशति रहने का विकल्प हो सकता है। हालाँकि लॉक-इन पीरियड के बाद नविश पर कोई गारंटी लागू नहीं होगी।
- **योगदान की सीमा:**
 - **अंशदान पर न्यूनतम और अधिकतम मौद्रिक सीमा** निर्धारित की जा सकती है। नविशकों को आकर्षक न्यूनतम गारंटीड रटिर्न होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

- **परिचय:**
 - केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) NPS की शुरुआत की गई।
 - वर्ष 2018 में इसे सुव्यवस्थित करने तथा और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंजूरी दी।
 - एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और वनियमिति किया जा रहा है।
 - पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।
- **संरचना:** एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है:
 - **टयिर- 1 खाता:**
 - यह गैर-नक़ासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्त खाता है, जिसमें संग्रहीत राशियों को ग्राहक के विकल्प के अनुसार नविश किया जाता है।
 - **टयिर- 2 खाता:**
 - यह एक सवैचछिक नक़ासी योग्य खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टयिर-1 खाता हो।
 - अभिदाता इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत राशियों को निकालने के लिये स्वतंत्र है।
- **लाभार्थी:**
 - एनपीएस मई 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।
 - 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक (नविशी और अनविशी दोनों) एनपीएस में शामिल हो सकता है।
 - हालाँकि **OCI (भारत के परवासी नागरिक)** और **PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति)** कार्डधारक तथा हिंदू अवभाजति परिवार (HUF) NPS खाते खोलने के लिये पात्र नहीं हैं।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण:

- **परिचय:**
 - यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थित विकास को वनियमिति करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।
 - यह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के अधीन काम करता है।
- **कार्य:**
 - यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेजर, सेंटरल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) आदिकी नयुक्तिका कार्य करता है।
 - यह NPS के तहत पेंशन उद्योग को विकसित करने, बढ़ावा देने और नयित्ति करने का कार्य भी करता है तथा APY का प्रशासन भी करता है।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

भारत-रूस सैन्य संबंध

प्रलिमिंस के लिये:

रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऑपरेशन गंगा, भारत द्वारा रूस से खरीदे गए विभिन्न रक्षा उपकरण, प्रोजेक्ट 75-I

मेन्स के लिये:

रक्षा प्रौद्योगिकी, द्विपक्षीय समूह एवं समझौते, रूस के साथ भारत के रणनीतिक संबंध, रूस-यूक्रेन संघर्ष

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्रों की निकासी का अभियान (ऑपरेशन गंगा) भारत पर यूक्रेन-रूस युद्ध का सबसे तात्कालिक प्रभाव है। हालाँकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के दीर्घकालिक नहितार्थ अभी सामने आने शेष हैं।

- उदाहरण के लिये एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना और दूसरी तरफ रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे एवं रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना।
- इसका भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा व्यापार पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।



भारत-रूस रक्षा संबंधों का इतिहास:

- भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने हथियारों के आयात के लिये लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर था।
- हालाँकि समय के साथ यह निर्भरता कम हो गई और 1970 के दशक के बाद से भारत USSR (अब रूस) से कई हथियार प्रणालियों का आयात कर रहा था, जिससे यह दशकों तक देश का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बन गया।
- रूस ने भारत को कुछ सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हथियार प्रदान किये हैं, जिनकी भारत को समय-समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है, इसमें परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू जेट और मिसाइल शामिल हैं।
 - एक अनुमान के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों में रूसी मूल के हथियारों और प्लेटफॉर्मों की हस्तिसेदारी 85% तक है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है।
- हथियारों के हस्तांतरण के मामले में रूस के लिये भारत सबसे बड़ा आयातक है।
 - वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच रूस, भारत को हथियारों के आयात के 66.5% हस्तिसे के लिये उत्तरदायी था।
- वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच भारत को हथियारों के आयात में रूस की हस्तिसेदारी लगभग 50% तक कम हो गई थी, लेकिन यह अभी भी सबसे बड़ा एकल आयातक बना हुआ है।

भारत, रूस से कौन-से रक्षा उपकरण खरीदता है?

- पनडुब्बियाँ: भारत को अपनी पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ से ही प्राप्त हुई थी।
 - USSR से खरीदी गई पहली फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी ने वर्ष 1967 में आईएनएस कलवरी के रूप में भारतीय सेना में प्रवेश किया था।

- भारतीय नौसेना के पास कुल 16 पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से आठ सोवियत मूल की कलौ श्रेणी की हैं।
- भारत के पास चार में से एक स्वदेश निर्मित परमाणु बैलस्टिक पनडुब्बी ([आईएनएस अरिहंत](#)) है, हालाँकि जिन्हें विकसित किया जा रहा है उनमें से कई रूसी तकनीकी पर आधारित हैं।
- **फ्रिगेट और गाइडेड-मिसाइल डस्ट्रॉयर:** नौसेना के 10 गाइडेड-मिसाइल वधिवंस्क में से चार रूसी काशीन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से छह [रूसी तलवार श्रेणी](#) के हैं।
- **वमिन वाहक:** भारत की सेवा में एकमात्र वमिन वाहक [आईएनएस वकिरमादित्य एक](#) सोवियत निर्मित कीव-श्रेणी का पोत है जो वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- **मिसाइल कार्यक्रम:** भारत का महत्त्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम रूस या सोवियत संघ की मदद से विकसित किया गया था।
 - भारत जल्द ही जिस [ब्रह्मोस मिसाइल](#) का नरियात शुरू करेगा, उसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **लड़ाकू वमिन:** भारतीय वायुसेना का 667-वमिन फाइटर ग्राउंड अटैक (FGA) बेड़ा 71% रूसी मूल (39% Su-30s [\(सुखोई\)](#), 22% MiG-21s, 9% MiG-29s) का है। सेवा में शामिल सभी छह एयर टैंकर रूस निर्मित [IL-78s](#) हैं।
- **हथियार और गोला-बारूद:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) के अनुसार, भारत का वर्तमान सैन्य शस्त्रागार रूस द्वारा निर्मित या डिज़ाइन किये गए उपकरणों से भरा हुआ है।
- **भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक** मुख्य रूप से रूसी T-72M1 (66%) और T-90S (30%) से बना है।
- **भारत के लिये अनुकूल रूसी सैन्य नरियात:** भारत में रूस का अधिकांश प्रभाव हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने की उसकी सम्मति के कारण है जैसी कोई अन्य देश भारत को नरियात नहीं करेगा।
 - अमेरिका केवल गैर-घातक रक्षा तकनीक प्रदान करता है जैसे [सी-130जे सुपर हरक्यूलस](#), [सी-13 ग्लोबमास्टर](#), [पी-8आई पोसीडॉन](#) आदि।
 - जबकि रूस [ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल](#), [एस-400 एंटी-मिसाइल सिस्टम](#) जैसी उच्च तकनीक मुहैया कराता है।
 - रूस भी अपेक्षाकृत आकर्षक दरों पर उन्नत हथियारों की पेशकश जारी रखता है।

सैन्य आपूर्ति पर रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

- फलिहाल भारत और रूस के बीच दो बड़े रक्षा सौदे हैं जिन पर मौजूदा संकट का प्रभाव पड़ सकता है।
- **S-400 ट्रायम्फ एयर-डिफेंस सिस्टम डील:**
 - यह सौदा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खतरे में है, यहाँ तक कि अमेरिका ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है।
 - हालाँकि रूस पर नए दौर के प्रतिबंध इस सौदे को खतरे में डाल सकते हैं।
- **संयुक्त पनडुब्बी के विकास की योजना:** रूस चार अन्य अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं के साथ [प्रोजेक्ट-75-1](#) के तहत नौसेना हेतु छह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP- संचालित) पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिये भी प्रयासरत है।
 - भारत दो परमाणु-बैलस्टिक पनडुब्बियों- चक्र 3 ([Chakra 3](#)) और चक्र 4 ([Chakra 4](#)) को पट्टे पर देने हेतु रूस के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें से पहली पनडुब्बी की आपूर्ति वर्ष 2025 तक होने की उम्मीद है।

हथियारों के आयात में विविधता लाने के लिये भारत की योजनाएँ:

- भारत द्वारा पछिले कुछ वर्षों में न केवल अन्य देशों में बल्कि घरेलू स्तर पर भी अपने हथियार प्लेटफॉर्म बेस का विस्तार करने के लिये प्रयास किया गया है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने पछिले वर्ष अपनी अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि भारत द्वारा वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है।
- वर्ष 2011-15 तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश था, लेकिन वर्ष 2016-20 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को किये गए हथियारों का आयात पछिले पाँच साल की अवधि की तुलना में 46% कम था जिससे वर्ष 2016-20 में यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश बन गया।
- वर्ष 2016-20 तक फ्रांस और इज़रायल भारत के लिये दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश थे।

आगे की राह

- जैसा कि पाकिस्तान और चीन को भारत बढ़ते खतरे के रूप में देखता है, साथ ही भारत की स्वयं की प्रमुख हथियारों का उत्पादन करने की महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, इसलिये भारत हथियारों के आयात को कम करने हेतु बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की योजना बना रहा है।
- आने वाले पाँच वर्षों में लड़ाकू वमिनों, वायु रक्षा प्रणालियों, जहाज़ों और पनडुब्बियों की उत्कृष्ट डिलीवरी के कारण भारत के हथियारों के नरियात में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इसलिये भारत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने आधार में विविधता लाए, किसी एक राष्ट्र पर बहुत अधिक निर्भर न हो, क्योंकि यह एक ऐसा लेवरेज (Leverage) निर्मित कर सकता है जिसका हथियार आयातक देश द्वारा भारत का शोषण किया जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

